

in order to earn foreign exchange by exporting Textile commodities in the financial year of 1970-71 and also in the year of 1971-72;

(b) which are the companies that received subsidies directly or indirectly for promotion of export trade in cotton-textile articles manufactured in India; and

(c) the different methods of granting such subsidies viz., (1) financial aid, (2) tariff relief and loans, total amount of money spent under these heads in the last two financial years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) to (c). Government does not give any subsidy directly to exporters of cotton textiles. However, Government gives to the Indian Cotton Mills' Federation a grant from the Marketing Development Fund at the rate of 5 per cent of the f.o.b. value on exported cotton textiles by way of compensation to cover a certain amount of non-refundable taxes on such textiles. During grant disbursed to the Indian Cotton Mills' Federation amounted to Rs. 5.49 crores and Rs. 5.35 crores respectively. No loans were granted. Drawback of duties are admissible at specified rates in respect of cotton textiles exported from the country. These drawbacks can be claimed by all exporters.

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई व्यवस्था

5454. श्री मूलचन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक गाइडों के प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो कहां-कहां पर यह व्यवस्था की गई है और उस पर सन् 1972-73 में कुल कितना खर्च किया गया है; और

(ख) यह प्रशिक्षण किन योजनाओं वाले व्यक्ति पा सकते हैं और क्या उन्हें प्रशिक्षण के बाद परीक्षा भी देनी होती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। वर्ष 1972-73 के दौरान पर्यटन विभाग ने मद्रास और कोचीन में भारत सरकार के स्थानीय पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से क्रमशः 4390/- रुपये और 3920/- रुपये की लागत से एक-एक गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

(ख) प्रशिक्षण के लिए 'ग्रेजुएटों' को लिया जाता है तथा विदेशी भाषाओं में निपणात व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम-प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर लिखित और मौखिक परीक्षाएँ ली जाती हैं।

पश्चिमी चाय बागान का सरकारीकरण

5455. श्री मूलचन्द डागा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय निगम ने पश्चिमी चाय बागान को कब अपने नियंत्रण में लिया और किस स्थिति में;

(ख) क्या 144.82 एकड़ भूमि पर किसी विदेशी सरकार का कब्जा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिमी चाय बागान, भारत सरकार द्वारा खरीद लिया गया है और वह उसके स्वामित्व में है।

(ख) जी हां।

(ग) बंगला देश सरकार, जो कि पुनर्निर्माण तथा पुनर्बाँस के द्वात्कालिक महान कार्यों में लगी हुई है के सामने इस